Out of lakhs of Central Government employees, only 15,000 employees of the Printing Wing are not being paid bonus for 1982-83.

I call upon the Government to fianalise the bonus formula immediately to include the employees of the stationery offices in the bonus scheme, to pay bonus for the year 1979-80 and the balance amount for the years 1980-81 and 1981-82 and also to pay bonus to the employees of the Government of India Presses and the stationery offices for the year 1932-83 without any delay.

(iii) Restoration of areas known as Blocks I and II to the Jaintia Hills districts of Meghalaya.

SHRI BAJUBON R. KHARLUKHI (Shillong) : In 1953, areas covered by Block I and II in the Jaintia Hills District, presently forming part of the State of Meghalaya, were given away to the Mikir Hills, now known as Karbi Anglong and presently forming part of the State of Assam.

The areas are predominantly inhabited by the Pnar people, speaking the Jaintia dialect and are culturally bound up with the culture of the Jaintia people.

The current feeling prevalent among the people of the Jaintia Hills District in particular and of the entire tribal people of Meghalaya in general is that the transfer of such areas was done in a manner that the sentiment of the people was not taken into consideration.

Following the carving out of the State of Meghalaya from Assam in 1972, the demand for the restoration of the said areas to the Jaintia Hills District has been gaining momentum.

In accordance with the Constitution of India, Parliament is the competent legislative authority to increase or reduce the boundaries of a State and in the process of giving as definite shape to that, the ethnic and linguistic realities are to be taken into consideration.

I urge upon the Government of India to take suitable legislative measures as would restore Block I and II to the Jaintia Hills District.

(iv) Need to declare support price of Jowar and to ensure its procurement

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछड़े प्रदेश जैसे राजस्थान व मध्य प्रदेश तथा आदिवासी क्षेत्रों में किसान खरीफ की फसल ज्वार व मक्का पर ही आश्रित रहते हैं, व भूमि की किस्म बारानी होने के कारण वर्ष में केवल एक ही फसल ले पाते हैं। इस वर्ष समय-समय पर अच्छी व अनुकूल वर्षा के कारण ज्वार की फसलें बहुत अच्छी हुई हैं परन्तु इस वर्ष अच्छी फसल के कारण जैसे ही ज्वार की मंडियों में आना शुरू हुआ, ज्वार के भाव गिरते जा रहे हैं व इस समय मंडियों में औसतन किस्म की ज्वार का भाव 100 रुपये से 102 रुपये प्रति क्विंटल ही रह गया है। सरकार ने इस वर्ष के लिए ज्वार का समर्थन मूल्य 124 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया है, परन्तु समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद की घोषणा न होने के कारण किसान 100 और 102 रुपये प्रति क्विंटल पर ज्वार को मंडियों में बेचने को विवश हो रहा है। इस प्रकार उसकी विवशता का अनुचित लाभ उठाया जा रहा है। भारत सरकार का यह तर्क कि ज्वार ग्रामीण क्षेत्रों में ही उपभोग की जाती है तथा इसके भंडारण की आयु अवधि कम होती है, इसलिए ज्वार खरीदने का भारत सरकार निर्णय नहीं ले सकती तथा आवश्यक हो तो राज्य सरकार स्वयं ही ज्वार को समर्थन मूल्य पर खरीद कर वितरण प्रणाली से बेचे, न्याय संगत तर्क नहीं है। इसलिए मैं भारत सरकार के खाद्य मंत्री से मांग करता हूं कि अविलम्ब समर्थन मूल्य 124 रुपया प्रति क्विंटल पर ज्वार खरीदने की घोषणा की जावे व उसके खरीद की व्यवस्था अविलम्ब की जावे।

(v) Need for encouragement to those who limit their families

SHRIMATI PRAMILA DANDAVATE (Bombay North Central) : Sir, According to the latest report of Food and Agriculture Committee of United Nations, India ranks

first in the malnourished and hungry people who number 210 million. In spite of the claimed increase in the production of food-grains, the number of hungry and malnourshed is also increasing.

This phenomenon of hunger in the midst of plenty is due to the population explosion. Unless we are successful in achieving zero growth rate of population, the fruits of development will never reach the poor.

Success and failure of Family planning programme is closely related to the status of women in the society. Traditional beliefs and undue importance to the son in the Indian society and prejudices against and misconception of men about vasectomy, are the major reasons for not achieving the desired target of bringing down the population growth-rate. So long as such beliefs persist, couples will continue to give birth to a number of daughters till they get a son and men would not come forward to undergo vasectomy.

I would, therefore, request the Government to consider to award a golden card to the couples who limit their families after one or two daughters and also after guaranteeing old age security.

(vi) Need to construct dams on rivers where floods cause a great havoc

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत जैसे देश में निरन्तर बढ़ते हुए बाढ़ प्रकोप के कारण नदियों के किनारे बसने वाले हजारों गांवों एवं नगरों की जनता को भी बाढ़ संकट झेलने के लिये विवश होना पड़ता है। सैंकड़ों व्यक्ति, पशु हर वर्ष मरते हैं, लाखों मीट्रिक टन खड़ी एवं पकी फसलें नेस्तनाबूद हो किसान की कमर तोड़ देती हैं।

उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर व उसके पास पड़ोस के अनेकों जनपद छोटी बड़ी नदियों से घिरे हैं। हर एक दो किलोमीटर पर कोई न कोई नदी छोटी बड़ी इस गाजरी क्षेत्र में है। बाढ़ प्रकोपों को रोकने के लिए केन्द्रीय जल आयोग तथा कृषि सिंचाई विभाग से संबंधित अनेकों अध्ययन दल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र तथा राहत कार्यों के अध्ययन के लिये जाते हैं पर बाढ़ का स्थायी हल ढूंढ़ने में कोई ठोस योजना बनाने में सरकार अभी तक असफल रही है। कुछ आटा, मिट्टी का तेल तथा नावों से बाढ़ में फंसे लोगों को निकालना व सेना को लगा देना ही केन्द्र व प्रदेशीय सरकारें समझती हैं कि हमने अपने कर्तव्य का पालन कर दिया। यह क्रम भी वर्षों से चल रहा है।

मेरी समझ से बाढ़ की विभीषिका का फैलाव बहुत दूर तक इसलिए भी हो गया है क्योंकि छोटी बड़ी सभी नदियों का धरातल मिट्टी से पटता जा रहा है, नदियां उथली हो गयी हैं। मेरी राय में जब तक नदियों को गहरा कराने, उनकी मिट्टी को निकाल कर किनारे बांधने और किनारों पर झाड़दार तथा बड़े वृक्षों के लगाने से मिट्टी के कटाव के रोकने के उपाय नहीं किये जाते तब तक बाढ़ की विभीषिका से बचना संभव नहीं।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इस दिशा में सर्वे करा कर एक बृहद योजना बनाये, यही बाढ़ से स्थाई रूप से बचने का उपाय है। इससे जहां बाढ़ से बचाव हो सकेगा, वहीं वृक्षारोपण की योजना सफल होगी तथा नदियों में सदा के लिये पानी रहेगा जो सिंचाई, मछली-पालन आदि कार्यों में उपयोग में आयेगा। इससे राष्ट्र की समृद्धि होगी।

(vii) Need to provide stable telecommunication facilities in flood prone coastal areas of Orissa

SHRI ARJUN SETHI (Bhadrak) : The House is well aware of the fact that the coastal districts of Orissa are prone to floods and cyclone almost every year. It has been the experience in the past that in the absence of stable telecommuncation facilites, dissemination of timely warning and ralief operations have been handicapped. This matter was brought to the notice of the Union Minister for Communications when he visited the State after the disastrous cyclone in 1982. It was requested that U. H. F. system should be provided on a number of intra-district and inter-district routes besides